

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग:

देहरादून: दिनांक-१३ जुलाई, २००६

विषय : नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कुण्डी खोला नाले के निकट मार्ग में सुरक्षात्मक कार्य हेतु वर्ष-२००६-०७ में वित्तीय, प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ के नगर अन्तर्गत रेवती जोशी के मकान के निकट कुण्डी खोला नाले के निकट मार्ग में सुरक्षात्मक कार्य हेतु रु०-२०.९० लाख की लागत के आगणन के विपरीत टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु०-१९.२८ लाख (रुपये उन्नीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- १- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- २- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- ३- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ४- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के अधीक्षण अभियंता/अधिशाली अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- ५- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन

१५४

गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

- 6- निर्माण एजेंसी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 7- यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को दिनांक 31-03-07 तक समर्पित कर दी जायेगी।
- 9- कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा।
- 10- स्वीकृत कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भू-तल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, जिसकी प्रतिलिपि शासन को भी उपलब्ध करा दी जाय।
- 11- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किशतों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किशत तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
- 12- आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 13- जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण ईकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- 14- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 15- विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
- 16- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।



- 17- कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
- 18- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता/अधिशारी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 19- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 20- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०-85/ XXVII(2)/2006, दिनांक-10 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।


सं० 158/V-श० वि०-06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्रीजी को मा० मंत्रीजी के सूचनार्थ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 6- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
- 7- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
- 8- अध्यक्ष/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़।
- 9- गार्ड फ़ाइल।



आज्ञा से,


(एन०के० जोशी)
अपर सचिव।